

से बहुत तसल्ली है लोगों को कि ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केरल में भी खास मिसालें कायम हुई हैं। यू पी का हाल दिल्ली जैसा ही है। कोई अच्छा नहीं है। वहां तो एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि कोई ठिकाना नहीं है। वहां तो यह हाल है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी को कुछ पैसे दे दिए और वह खामोश हो गया। वह भी इसी तबज्जह की मोहताज है जैसे दिल्ली है। यू पी में इस से ज्यादा ही कुछ होगा। कोई अच्छा काम मैं नहीं देख रहा हूँ।

मैं मरादाबाद से आता हूँ जहां मुसलमानों की वक्फ की जायदाद लाखों नहीं कराड़ों रुपये की होगी। कोई इस्तेमाल उस का नहीं होता। उल्टे और खर्चा गवर्नमेंट पर पड़ जाता है। डीफिशियेंसी रहती है। दिल्ली में तो अपना-अपना खर्च बोर्ड चला भी लेंते हैं लेकिन मरादाबाद में कमी रहती है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऊपर से करो। वक्फ भी वहां कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लखनऊ में बहुत बड़ी जायदाद वक्फ की है, इलाहाबाद, कानपुर में मैंने देखा है, काफी जायदाद है। तो यही मेरी गुजारिश है कि एक काम्प्रीहेन्सिव बिल ला कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे। गूडविल आप को मिलेगी, हमें तो कुछ मिलना नहीं है।

17.50 hrs.

STATEMENT RE: SALE OF TICKETS OF ASIAD TO MEMBERS OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BUTA SINGH): Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members of both the Houses for showing keen interest in the Ninth Asian Games to be held from 19th November.

The question relating to the sale of tickets to the hon. MPs to enable them and their family members to witness the

Games, has been engaging the attention of the Organising Committee and the Parliamentary Forum of Sports. The hon. Chairman, Rajya Sabha, hon. Speaker and you, Sir, have been taking keen interest in the subject. You have been very kind to give me a patient hearing and you have listened to various problems connected with the issue.

Sir, only just now, in your Chamber a meeting was held with the Members of the Parliamentary Forum of Sports. It has been decided in that meeting that the plan for sale of tickets of ASIAD to the MPs will be finalised on tenth i.e. Tuesday. Thereafter, the tickets will be sold in a manner and on dates to be announced later.

As on today, no ticket will be sold on 9th August as announced earlier.

17.51 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री कृष्ण वल्ल सुल्तानपुरी (शिमला) : उपलब्ध महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वक्फ प्रापर्टी है, उसका सारा का सारा इन्तजाम पंजाब, हरियाणा के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वहां के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। जब आप दिल्ली में इस संबंध में समय मांग रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी आप एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनायें, ताकि वहां की सारी की सारी प्रापर्टी को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल किया जा सके। मुसलमानों की आबादी वहां पर भी अधिक है, मेरे नहान जिला है, शिमला में भी है, सोलन में भी है और बिलासपुर में भी - वहां के मुसलमानों के लिए न पढाई का इन्तजाम ठीक प्रकार है और न ही और कोई सुविधायें हैं। उदाहरण वहां की सैकेण्ड लैंग्वेज है। वहां इस प्रकार की जनता प्रापर्टी है, उस पर मोमडन ने कब्जा कर रखा है और उससे जितनी कमाई होती है वे सब छी जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उससे आमदनी

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

होती है, वह बाकयदा नेशनलाइज करके आप उसका अपने सरकारी खजाने में रखें और उनका ठीक प्रकार से विस्तार किया जाए। मेरे पास एक ड्रैप्टेशन आया था, जिस ने यह मांग की कि कम से कम आप एक मालवी लायें, ताकि नमाज तो हम पढ़ना सीख लें। लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जिस तरह से मंदिर के मालिक हिमाचल प्रदेश के अन्दर हैं। मंदिरों की जितनी कमाई आती है, वे सब अपने हिसाब से करते हैं। गुरूद्वारों का संचालन गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा किया जाता है और उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। जब गरीबों के ख्याल करने का प्रश्न आता है तो वे कान में उंगली डाल कर नमाज पढ़ते हैं, उनको मुसलमानों की तरहकी का कोई ख्याल नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम वक्फ प्रापर्टी का प्रबन्ध ठीक प्रकार से करना चाहते हैं, तो हमें इसकी कमाई का बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। जिसके लिए वे जायदाद है। जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्धेरगदीं हो रही है, तो इस की जांच होनी चाहिए और कान आदमी ऐसा करता है, उस को देखना चाहिये।

एक माननीय सवस्य : सरकार करती है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : और भी हो सकते हैं बीच में। वक्फ बोर्ड के आदमी भी उस में शामिल हो सकते हैं। सरकार अकेले यह नहीं करती है लेकिन सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूँ कि सरकार इस हाउस में ऐसा बिल लाए कि हर राज्य में, हर स्टेट में अलेहदा-अलेहदा वक्फ बोर्ड होने चाहिए ताकि वहाँ की प्रापर्टी की हिफाजत हो सके।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आदमी शिमला में मस्जिद में रहते हैं, उन की बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर एक मालवी ने कब्जा किया हुआ है और वह अम्बाले में रहता है और उन से किराया चार्ज करता है और उन को कोई सुविधा नहीं है। जो मुसलमान वहाँ पर काश्मीर से आते हैं या दूसरे प्रान्तों से वहाँ पर जाते हैं, उन को वहाँ पर रहने के लिये जगह नहीं मिलती।

वहाँ पर महेजे एक मस्जिद है, जहाँ पर इन्तजाम ठीक तरह का नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली हो या शिमला हो या अन्य बड़े शहर हों, वहाँ पर मुसलमानों की प्रापर्टी का यह हाल है: हमारे यहाँ डक्साई में जाएं तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है कसौली में जाए, तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है, डलहोजी में जाए, तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है और स्पाडू में जाएं तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है और ये जितने केन्टोन्मेंट बोर्ड में हैं, वहाँ पर कोई चीज आप बना नहीं सकते हैं। 1924 का जो एक्ट है, उस के मूताबिक केन्ट में कोई मकान नहीं बना सकता है, कोई जायदाद ठीक नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जमाने का यह पुराना एक्ट है और इस को बदलना होगा। कई लोग वैसे ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कानून बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है और हम नया कानून, बना कर लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं जिससे उन लोगों में यह विश्वास हो कि यह जो सरकार है, यह उन के द्वारे में भी कुछ सुचुती है। उन को जो जायदाद है, उस की हिफाजत हमें करनी चाहिए और ठीक प्रकार से उसका प्रयोग हो और मिसयूज न हो, यह हमें देखना चाहिए।

इतना कह कर मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए और यह जो बिल आप लाए हैं, इस की मैं ताईद करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Ratansinh Rajda may speak.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are going to pass this Bill. Then only we are going to adjourn. The Business Advisory Committee has already decided. It has been announced also.

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): Sir, near chaotic conditions prevail in India with regard to Wakf properties. That is the situation throughout India. Sir, the present amending Bill has been brought about to extend the limitation because formerly it was up to

31.12.1980. Now, unauthorised occupations are on a very large scale as far as wakf properties are concerned. To enable the recovery of those unauthorised possessions and to enable them to file suits for the recovery, this amendment has been brought about and it is a commendable step taken by the Government. The only thing is that the various speeches that have been made here bring one thing to light and that is whether this Government has got a resolute will, a determination to see that a comprehensive Bill is brought about and all the injustices done so far, which have accumulated all these years, are put to a naught and justice is done as far as all those wakf properties are concerned.

Sir, unauthorised occupations of Wakf properties are on a very large scale. Unfortunately in a place like Delhi, the Capital of India, the survey work is not complete. We do not know how many properties are there, what is their total value or what will be the total valuation of all these properties. It may amount to crores of rupees and in the absence of any survey, one does not know what is happening to all those unauthorised occupations. Nobody is challenging these unauthorised occupants and they run away with their mischief. All these years they have been the beneficiaries without any legal title to all those properties and for that it is very much necessary to regulate and to extend the period of limitation so that we get these properties. It is necessary that this limitation is extended so that within the next five years up to 1985 we will cope up with the situation and all these properties which are under unauthorised occupation are recovered, their possession is taken back and recovery is effected from the clutches of unauthorised occupants.

18.00 hrs.

Sir, I think and I hope that this would be the last extension and during this period, the Government will be able to cope up with the situation and for that energetic and vigorous steps will have to be taken. I hope, this would be the last amendment which will solve

this problem to the satisfaction of the minority community in this country.

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Jamilur Rahman.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to call all of you. We are going to complete this Bill and then only, we will adjourn.

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): Hon. Deputy Speaker, Sir, are you going to extend the time?

MR DEPUTY-SPEAKER: It is already extended. We are going to complete this Bill. All Members whose names are before me will be called to speak, except Shri Sunder Singh because his name is not here!

श्री जमीलूरहमान (किशनगंज) : मंत्रीमंडली स्पीकर साहब, मैं आपका शक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका इनायत फरमाया है कि मैं इस नन्हे-मुन्हे से वक्फ़ तर-सीमी दिल पर कुछ कहूँ। मैं इस दिल का हरमकदम करता हूँ और साथ-साथ इसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं चंद बातें कहे वगैर नहीं रह सकता। . . . (व्यवधान) . . .

मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ :-

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।  
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्च नहीं होता।

मैंने कहने का मकसद यही है कि इस छोटे-मोटे बिल लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अगर वक्फ़ जायदादों का मारने हिन्दूस्तान में ठीक से सर्वे हो जाए, जाँ कि अब तक नहीं हो पाया है तो वे मंत्री स्थान में 15 हजार करोड़ रुपये की है। लेकिन 35 वर्ष का अर्सा हो गया, यह अब तक नहीं हो पाया है। यह अफसोसनाक बात है और यह बात जबकि मैं इस सदन में खड़े हो कर कह रहा हूँ तो बहुत ही इत्मीनान और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यह सिर्फ मंत्री ही आवाज नहीं है, यह करोड़ों मुसलमानों की आवाज है।

[श्री जमीलूरहमान]

मेरे स्थाल से अगर वक्फ जायदादों का मसला हल हो जाए तो इस मुल्क का मुसलमान मदद के लिए सरकार की तरफ आंख नहीं उठायेगा। 1947 के बाद से बराबर शोर-शरावा मुसलमानों की तरफ से हो रहा है और कोई मर्तबा इस सवाल को उठाया गया। लेकिन कहें तो किस को कहें।

आनदेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हूँ कि इस मुल्क में सेक्युलरिज्म और वक्फ के चार सब से बड़े दुश्मन हैं। नम्बर एक - लेण्ड एण्ड डवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा डी. डी. ए., तीसरे वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री इन्कलूडिंग रिहबिलिटेशन मिनिस्ट्री और चौथे आरकेलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया।

मुल्क में 1947 में हालात नाजूक थे। उस वक्त हम छोटे-मोटे थे, हम को क्या पता था कि यह क्या चीज है। उन नाजूक हालात में मुसलमानों ने अपने को द्वातरे में महसूस किया और वे अपनी-अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गये। 1971 में मुसलमानों में एत्माद आया जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयीं तो वे (मुसलमान) अपनी अपनी जगहों पर जा कर फिर बसें और उन्होंने अपनी-अपनी जगहों को हासिल करने का सवाल उठाया। लेकिन हुआ क्या? अभी तक उन जायदादों को रिलीज नहीं किया गया। इस के लिए हम किस को ब्लेम करें, किस को कहें! यह बात मैं आपके जरिये सरकार को कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ।

दूसरी बात यह है कि 1974 में बनी कमेट्री की इन्वॉरिमा रिपोर्ट आयी थी। 1976 में रिपोर्ट सबमिट हुई, छः साल छः साल हो गए हैं, अभी तक जेरे गौर है। कब तक जेरे गौर होगा। उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। 1985 तक आपने लिमिटेशन बढ़ाने का कहा है। क्या मकसद है? पहले बात दिल और दिमाग में आती है, उसके बाद चेहरे पर और बाद में हाथ-पैर एक्शन में आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब,

दिल्ली भारत का दिल है, अगर यहां पर कोई बात होती है तो उसकी हवा सारे देश में फैलती है। यहां पर सैकड़ों दूसरे गैर-मुस्लिम लोग रहते हैं, वे भी इस बात को देखते हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी भी बात होती है तो पूरे हिन्दूस्तान में उसका जिक्र होता है। तुर्कमान गेट की घटना सही थी या गलत, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 1977 को इस घटना का असर जो हिन्दूस्तान पर पड़ा है वह मेरे और आपके सामने है। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। बनी-कमेट्री की रिपोर्ट को छः साल हो गए, क्यों नहीं एक कंघ्रहंसिव बिल आता है। 1985 तक एक्सटेंड करने का क्या मकसद है? ताकि जो बची-खुची वक्फ जायदाद दिल्ली में है वे भी साफ हो जाएं।

रिक्वरी की कोई बात नहीं आई कि जायदाद वक्फ को या मुसलमानों को वापिस हों, इसकी बात नहीं आई। एक्सटेंशन देने से क्या होगा - इसका मतलब यह होगा कि जैसे शेखूसराय और यूसफसराय में काब्रुस्तान था, उस पर चारों तरफ डी डी. ए. का कब्जा हो गया है। एक मस्जिद भाँठ जहाँ पहले मुसलमान बसते थे, वे वापिस आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट का कब्जा है। कोई सनवाई नहीं हो रही है और न मस्जिद वापिस हुई है। पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद वस टर्मिनीनल के पास टूट-फूट गई है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। पहाड़गंज की मस्जिद में होटल बन गया है। एक दर्द हो तो आपको बताएं, यह तो लाइलाज मर्ज है।

डिप्टी स्पीकर साहब आप बड़े साफ जहन के आदमी हैं। आप उस स्टेट से आते हैं जहाँ पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए उस बात का असर आप पर भी है। आप खूले जहन के पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैंने ये जो चार डिपार्टमेंट बताए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं, जिनका एक उसूल मालूम होता है, कि उनकी हरकतों से यह मालूम होता है कि जैसे कि वे चाहते हैं कि अक्लियत हिन्दूस्तान में न रहे, उनकी जायदाद न रहे। वक्फ को 'डेडी-

केशन आफ गाड' माना है । एक्ट के मूला-  
विक देखा जाए :-

“(a) “beneficiary” means a person or object for whose benefit a wakf is created and include religious, pious and charitable objects and any other objects of public utility sanctioned by the Muslim law;”

उसके नीचे दिया है --

“(i) Any person who has a right to worship or to perform any religious rite in a mosque, idgah, imambara, dargah, Khangah, Maqbara, grave-yard or any other religious institution connected with the wakf or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf;”

आप मोहम्मडन एक्ट में देखेंगे, एक मकसद के तहत वक्फ किया जाता है । उसमें दो किस्म के वक्फ होते हैं - 'फारदि पीपुल इन दी नेम आफ गाड' और दूसरा होता है औलादों के लिए । तो क्या ये चारों डिपार्ट-मेंट क्या इन दोनों चीजों में आते हैं । हमारे हिस्सेदार ये डिपार्टमेंट नहीं हैं और नही यह वक्फ अहले औलाद की कैटे-गरी में आते हैं । चाहे कोई भी डिपार्ट-मेंट हों ।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि समय मिलना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आप पूरा बिल लाइए और इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि वे मुसलमानों की वक्फ जायदाद बच सकें ! जिस परपज के लिए वे जायदाद दी गई है, उनको पूरा किया जा सके । स्कूल बनें, कालेज बनें, अस्पताल बनें, डिवेलपमेंट के लिए उप-योग किया जाए । अस्पताल बनें लेडी स्कूल बनें, उनके डिवेलपमेंट के काम हों ।

मैं आंकड़ा दे रहा हूँ । वक्फों की हालत सारे मुल्क में बुरी है, लेकिन दिल्ली में तो और भी बुरी हालत है । इतनी अफरा-तफरी क्यों मची हुई है? किस वक्त जमीन बेच कर कहीं कोई फरार हो जाएगा पता ही नहीं चलता । सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसको वापिस लिया जा सके । आप आंकड़ा देखें । 134 जायदाद वर्क्स एंड हाउसिंग

के तहत डी. डी. ए. के कब्जे में इस वक्त भी है । 108 जायदाद लैंड एंड डिवेलपमेंट के कब्जे में है । क्यों इसके बारे में कर्वाई नहीं हुई है । जब 7-8 मंजिला इमारतें बन जाएंगी तब नोड टूटेगी क्या ? क्या मतलब है इसका ? मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ । भिखारो नहीं हूँ । अपना हक मांगता हूँ । इन वक्फ की जायदादों को वापिस कीजिए । इनको लेने वाले दूसरे आदमी नहीं हो सकते हैं, ये चार डिपार्टमेंट लेने वाले नहीं हो सकते हैं । जो वारिस है वही हो सकते हैं । पंद्रह करांड मुसलमान हिन्दुस्तान के इनके वारिस हैं ।

अभी तक आप ने सर्वे नहीं किया है इन जायदादों का । कम से कम दिल्ली की जायदादों का आए सर्वे तो बराबे और सदन को जो नतीजा नकले दताएं कि देश में कितनी वक्फ की जायदाद है और कितने करांड की है और दिल्ली में कितनी है और कितने करांड की है ।

MR DEPUTY SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill comes.

प्रेस के बारे में बड़ी लम्बी बात हुई है आज । यह कहा जाता है कि बिहार सर-कार ने 292 (ए) ला कर प्रेस के अधिकार में हस्तक्षेप किया है । कालिंग एट्रेशन पहले पहर सदन में आया था । एक दो प्रश्न मैं उनके लिये भी रहना चाहता हूँ । सदन में उसका जवाब तो नहीं मिल पाएगा । मौलिक अधिकारों का मैं बड़ा हामी हूँ अलम्बरदार हूँ । प्रेस को नेश-नल प्रेस कहा जाता है लेकिन मैं तो इसको कॉर्पोरेटलिस्टिक प्रेस मानता हूँ मैं चाहता हूँ कि बताया जाए कि अकालियतों की जायदादों पर जिस कद्र जुल्म हो रहा है और उनकी इकानॉमिक और सोशल हालत जो है, उसकी डिवेलपमेंट के लिए भी क्या आज तक यह नाम निहावी नेशनल प्रेस ने कुछ लिखा है । क्या हम हिन्दुस्तान के

[श्री जमीलूरहमान]

शहरी नहीं है ? जब कोई फिसाद का मामला पैदा होता है, गड़बड़ो पैदा होती है, प्रेस वालों को पेट्रोडालर नजर आते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी यह भी बताया है कि कितने मुसलमान और कितने गैर मुसलमान मुल्क के बाहर हों और वे कितने पेट्रोडालर अलग-अलग हिन्दुस्तान में भंजते हैं? जब पेट्रोडालर का इलजाम लगाया जाता है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने मुसलमान हिन्दुस्तान के बाहर हैं और कितने गैर मुसलमान बाहर हैं और दोनों अलग-अलग कितने पेट्रो डालर हिन्दुस्तान में लाते हैं या भंजते हैं। प्रेस की आजादी का मैं बड़ा हामी हूँ अलम्बरदार हूँ। 1971 से 1977 तक मैं मैम्बर रहा हूँ। पार्लियामेंट की कार्यवाही गवाह है कि मैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्स का हमेशा हामी रहा हूँ। गुजराल साहब मिनिस्टर थे, दीगर लोग भी रहे, शक्ल जी भी थे, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं कितना बड़ा अलम्बरदार स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स का रहा हूँ और इस चीज को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स भी साबित कर देगी। लेकिन यह नाम निहावी नेशनल प्रेस डालों को कौन समझाए।

दरगाह किलोखेड़ी का मामला दिल्ली में अभी भी पींडंग है। दूसरा कोई दर गजर कर सकता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मामले को दरगजर कर दिया जाए। यह अहम मामला है। इसके दरगजर होने भी नहीं दंगा। 29 तारीख को पिछले महीने को मैं वहाँ गया था।

मैं दरगाह शरीफ गया था। किलोखेड़ी मैं दरगाह के अलावा छोटे-छोटे कविस्थान भी हैं। डी. डी. ए. के वृद्धांशर शाह में चल रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, चार पांच डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर हम लोगों का खातमा हों जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं इतना कमजोर-जान नहीं हूँ, मैं आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूँ हिन्दुस्तान से, चाहे वे कितनी कोशिश करें, चाहे कितना दंगा-फसाद करें। हम जिस नेता पर यकीन करते हैं, उसका

ईमान है सैशलिज्म और स्केलरिज्म पर।

MR DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

अगर रीएक्शनरी फोर्सिज हमें डराना धमकाना चाहती है, तो जमीलूरहमान और उसको सात पुस्तों के लोग डरने वाले नहीं हैं।

किलोखेड़ी का मजार एक मनबेरिक मकाम है। अभी पिछले महीने 29 तारीख को मैं गया था। मजार में जितनी कब्रें हैं, सिवाए पीर साहब के मजार, को सब तोड़ फाड़ कर बराबर कर दी गई है। पीर के पानी का जो कुआं था, उसके तोड़ कर बराबर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां चार पीपल के दरख्त हैं। उनके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है और मजार को बन्द कर दिया गया है। आप गौर फरमाएँ कि यह किस बात का संकेत है, किस बात की तरफ इशारा है कि एक तरफ तो कब्रों को खत्म किया जा रहा है, कूएँ को खत्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ पीपल के दरख्तों के चारों तरफ चबूतरा बना कर ढोल बजाया जा रहा है। इसके मानी यं है कि फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

इस लिए मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर एक कांफ्रि-हेंसिव बिल लाएं। शेर के मुताबिक कहीं ऐसा न हो कि "हम लाक हो जाएंगे तारी जल्फ के सर होने तक"। सरकार लिमिटेशन पीरियेड का बड़ानी जाये और डी. डी. ए., आक्रोआलोचिकल डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट सब वक्फ की खाली जमीनों और मकानों पर कब्जा करता जाए और कोई जायदाद ही न बचे, तो मुकदमा किस बात का? यह बात मैं संकेत के तौर पर कह रहा हूँ।

अभी आनरबल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली वकफ बोर्ड एडीमिनिस्ट्रेशन को एपरोच किया और इस लिए जरूरत पड़ी कि वकफ एक्ट में एमंडमेंट ला कर उसको लिमिटेशन 1985 के आखिर तक बढ़ा दिया जाए। महतरम वजीर साहब को शिकवा किससे है? - हम लोगों से या इस सदन से? जो आदमी मुजरिम के कटघरे में खड़ा है, जो इस काम को करा रहा है, लैंड डेवेलपमेंट विंग वही एपरोच कर रहा है कि इस एक्सट को बढ़ाया जाए। इसकी नीयत बहुत खराब है कि टाइम को एक्सटेंड कर के माँका मिले और एक्वायर कर के मुसलमानों की सारी जायदाद को नेस्त-नाबूद कर दिया जाए, न रहेंगे बांस न बजेंगी बांसुरी।

मेरा दिल चाहता है कि हर एक को उसका जायज हक मिलना चाहिए। यही हमारी पार्टी का असूल है और यही हमारी नेता का असूल है और हम और हमारी पार्टी इस के बारे में किसी से कामप्रोमाइस करने के लिए तैयार नहीं है। हम, हमारी पार्टी और हमारी नेता इस गलत रवैये के खिलाफ हर वह कदम उठा सकते हैं, जो जायज और दुरूस्त है।

شہری جمہل الرحمن (کشن گلج) :

محترم قیدی اسپیکر صاحب - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں اس نلے ملے سے وقف ترمیمی بل پر کچھ کہوں - میں اس بل کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو سہورق کرتا ہوں - لیکن میں چلن باتیں کہے بغیر نہیں رہ سکتا - (انٹروپشن) . . . .

میں آپ سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں -

دہم آہ بھی کرتے ہیں  
تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں

تو چرچا نہیں ہوتا -

مہرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس چھوٹے موٹے بل لانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے - اگر وقف جائدادوں کا سارے ہندوستان میں ٹھہک سے سروے ہو جائے جو کہ اب تک نہیں ہو پایا ہے تو وہ مہرے خیال میں پندرہ ہزار کروڑ روپے کی ہیں - لیکن ۲۵ ورہں کا عرصہ ہو گیا ہے اب تک نہیں ہو پایا ہے - یہ انیسویں ناک بات ہے اور یہ بات جب کہ میں اس سदन میں کہنے ہو کر کہہ رہا ہوں تو بہت ہی اطمینان اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مہری ہی آواز نہیں ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کی آواز ہے -

مہرے خیال سے اگر وقف جائدادوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس ملک کا مسلمان مدد کے لئے سرکار کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا - ۱۹۴۷ء کے بعد سے برابر شور شرابا مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور کئی مرتبہ اس سوال کو اٹھایا گیا - لیکن کہیں تو اس کو کہیں -

آریبل قیدی اسپیکر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں سکولرزم اور وقف کے چار سب سے بڑے دشمن ہیں - نہر ایک لہندہ ایلیٹ قہرلوہیلک تیہارتمہلت - دلی

## [شرعی جمہل الرحمن]

ایڈ منسٹریشن دوسرا قی - قی - اے -  
تیسرے ورکس ایڈ ہاؤسنگ منسٹری  
انکوریٹنگ ری ہیبیلی ٹیشن منسٹری  
اور چوتھے آرگنولوجیکل ڈیپارٹمنٹ  
آف انڈیا -

ملک میں ۱۹۴۷ء میں حالات  
نازک تھے - اس وقت ہم چھوٹے موٹے  
تھے ہم کو کیا پتہ تھا کہ یہ کیا  
چیز ہے - ان نازک حالات میں  
مسلمانوں نے اپنے کو خطرے میں  
محسوس کیا اور وہ اپنی اپنی  
جگہوں سے دوسری جگہوں پر منتقل  
ہو گئے - ۱۹۷۱ء میں مسلمانوں  
میں اعتماد آیا جب کہ شہریت  
اندر گاندھی جوت کر آئیں تو وہ  
(مسلمان) اپنی اپنی جگہوں پر جا  
کر پور بسے اور انہوں نے اپنی اپنی  
جگہوں کو حاصل کرنے کا سوال اٹھایا -  
لیکن ہوا کیا - ابھی تک ان جائدادوں  
کو ریٹرن نہیں کیا گیا - اس کے لئے  
ہم کس کو بلوہ کریں کس کو کہیں -  
یہ بات میں آپ نے ذریعہ سے سرکار  
کو کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں -

دوسری بات یہ ہے کہ ۱۹۷۳ء  
میں برنی کمیٹی کی انٹیم ریپورٹ  
آئی تھی - ۱۹۷۶ء میں ریپورٹ سمیت  
ہوئی چھ سالہ چھ سال ہو گئے  
میں ابھی تک زیر فور ہے - کب  
تک فور ہوگا - اس کی کوئی سہما  
ہونی چاہئے لمیٹیشن ہونی چاہئے -

۱۹۷۵ء تک آپ نے لمیٹیشن پر ہانے  
کو کہا ہے کیا مقصد ہے - پہلے بات  
دل و دماغ میں آتی ہے اس کے بعد  
چہرے پر اور بعد میں ہانہ پھر  
ایکشن میں آتے ہیں - دیتی اسٹیٹنگ  
صاحب - دلی بھارت کا دل ہے اگر  
یہاں پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس  
کی ہوا سارے دیس میں پھیلتی  
ہے - یہاں پر سٹیٹنگ دوسرے غہر  
سوالک کے لوگ دھتے ہیں وہ بھی  
اس بات کو دیکھتے ہیں - اس لئے  
اگر تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو  
پورے ہندوستان میں اس کا ذکر ہوتا  
ہے - ترکمان گیت کی گھنٹا صبح  
تھی یا غلط اس بات میں میں  
نہیں جانا چاہتا لیکن ۱۹۷۷ء کی  
اس گھنٹا کا اثر جو ہندوستان پر پڑا  
ہے وہ مہرے اور آپ کے سامنے ہے -  
ان باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا -  
برنی کمیٹی کی ریپورٹ کو چھ سال  
ہو گئے کیوں نہیں ایک کمیٹی  
بل آتا ہے - ۱۹۸۵ء تک ایکسٹینڈ  
کرنے کا کیا مقصد ہے - تاکہ جو وقف  
کی بچی بچی جائدادیں دہلی  
میں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں -

دیکھو کی کوئی بات نہیں آئی  
کہ جائداد وقف کو یا مسلمانوں کو  
واپس ہوں اس کی بات نہیں آئی -  
ایکسٹینشن دیکھ سے کہا ہوگا اس کا  
مطلب یہ ہوگا کہ جسے شہر سرائے  
ور ہوصف سرائے میں ہندوستان تھا

اس پر چاروں طرف قی - قی - اے -  
 کا قبضہ ہو گیا ہے - ایک مسجد  
 مرنے والے ہے جہاں پہلے مسلمان بستے  
 تھے وہ واپس آگئے ہیں لیکن وہاں  
 پر آرکھولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کا قبضہ  
 ہے - کوئی سلوولی نہیں ہو رہی ہے -  
 اور نہ مسجد واپس ہوئی ہے - پرانی  
 دلی میں ایک مسجد بس ترمیم  
 کے پاس جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے  
 مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ  
 نہیں ہے - پہاڑ گلیج کی مسجد میں  
 ہرنٹل بن گیا ہے - ایک درد ہو تو  
 آپ کو بتائیں یہ تو لا علاج مرض ہے -

قبضہ اسی صاحب - آپ بڑے  
 صاف ذہن کے آدمی ہیں - آپ اس  
 اسٹیک سے آئے ہیں جہاں بڑے لکھ  
 لوگوں کی سہولت زیادہ ہے - اس لئے  
 اس بات کا اثر آپ پر بھی ہے - آپ  
 کہلے ذہن کے بڑے لکھ آدمی ہیں  
 لیکن میں نے یہ جو چار ڈیپارٹمنٹ  
 بنائیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں  
 جن کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ  
 ان کی حرکتوں سے یہ معلوم ہے کہ  
 جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقلیت  
 ہندوستان میں نہ رہے ان کی جائداد  
 نہ رہے - وقف کو وہ ڈیپارٹمنٹ آف  
 گائڈنس مانا ہے - ایکٹ کے مطابق  
 دیکھا جائے -

objects of public utility sanctioned by  
 the Muslim Law;"

اس کے نیچے دیا ہے -

"(i) Any person who has a right to  
 worship or to perform any religious  
 rite in a mosque, idgah, imambarah,  
 dargah, Khangah, Maqbara, grave-  
 yard or any other religious institution  
 connected with the wakf or to partici-  
 pate in any religious or charitable  
 institution under the Wakf;" .. .. .

آپ مہتمم ایکٹ میں دیکھیں گے  
 ایک مقصد کے تحت وقف کہا جاتا  
 ہے - اس میں دو قسم کے وقف ہوتے  
 ہیں - وہ دار دی پوریل ان دی نوم  
 آف گائڈنس اور دوسرا ہوتا ہے اولادوں  
 کے لئے - تو کہا یہ چاروں ڈیپارٹمنٹ  
 کہا ان دونوں چیزوں میں آتے ہیں -  
 حصہ دار یہ ڈیپارٹمنٹ نہیں ہیں  
 اور نہ ہی یہ وقف اہل اولاد کی  
 کھتھری میں آتے ہیں - چاہے کوئی  
 بھی ڈیپارٹمنٹ ہو -

اس لئے میں مرض کر رہا تھا  
 کہ سب ملنا چاہئے اور ہمارا پورا  
 سمیٹہ ہے لیکن آپ پورا بل لائے  
 اور اس طرح کی ویو سنٹھا کھجئے کہ  
 وہ مسلمانوں کی وقف جائدادیں بیچ  
 سکیں - جس پرپز کے لئے وہ جائدادیں  
 دی گئی ہیں ان کو پورا کہا جاسکے -  
 اسکول بلوں کالج بنیں ہسپتال  
 بنیں ڈیپارٹمنٹ کے لئے ایڈوگ کہا  
 جائے - ہسپتال بنیں لہذا اسکول  
 بنیں ان کے ڈیپارٹمنٹ کے کام ہوں -

"(a) beneficiary" means a person  
 or object for whose benefit a wakf is  
 created and include religious, pious  
 and charitable objects and any other

[شہری جمیل الرحمن]

میں آنکڑے دے رہا ہوں وقفوں  
 کی حالتیں سارے ملک میں بری ہے  
 دلی میں تو اور بھی بری حالت  
 ہے - اتلی افراندری کہوں سچی ہوئی  
 ہے کس وقت زمین بیچ کر لیں  
 کوئی فراہ ہو جائے گا پتہ ہی نہیں  
 چلتا - سرکار کے پاس کوئی سادھن  
 نہیں ہے کہ اس کو واپس لیا جا  
 سکے - آپ آنکڑا دیکھیں - ۱۳۴  
 جائدادیں ورکس ایجنٹ ہاؤسنگ کے  
 تحت تی - تی - اے - کے قبضے  
 میں اس وقت بھی ہیں - ۱۰۸  
 جائدادیں لیجنٹ ایجنٹ ڈیولپمنٹ کے  
 قبضے میں ہیں کہوں اس کے بارے  
 میں کاروائی نہیں ہوئی ہے - جب  
 سات آٹھ مڈلہ عمارتیں بن جائیںگی  
 تب نکلے تو گئے گی کیا - کیا مطالب  
 ہے اس کا - میں بھوک نہیں مانگ  
 رہا ہوں بھکاری نہیں ہوں - اپنا حق  
 مانگتا ہوں - ان وقف کی جائدادوں  
 کو واپس کھائے - ان کو لہنے والے  
 دوسرے آدمی نہیں ہو سکتے ہیں -  
 یہ چار ڈیپارٹمنٹ لہنے والے نہیں  
 ہو سکتے ہیں - جو وارث ہیں وہی  
 ہو سکتے ہیں - پندرہ کروڑ مسلمان  
 ہندوستان کے ان کے وارث ہیں -

ابھی آپ نے سروے نہیں کیا ہے  
 ان جائدادوں کا - کم سے کم دلی کی  
 جائدادوں کا آپ سروے تو کرائیں اور  
 سدن کو جو نچھہ نکلے بتائیں کہ

میں کتنی وقف کی جائدادیں  
 ہیں اور کتنے کروڑ کی ہیں اور دلی  
 میں کتنی ہیں اور کتنے کروڑ کی  
 ہیں

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray to God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill come.

پریس کے بارے میں بڑی لمبی  
 بات ہوئی ہے آج - یہ کہا جاتا ہے  
 کہ بہار سرکار نے (۱۹۲) (اے) لا کر  
 پریس کے ادھیکار میں مستکشیپ  
 کیا ہے - کالنگ ایڈمن پہلے پہل  
 سدن میں آیا تھا - ایک دو پرشن  
 میں ان کے لئے بھی رکھنا چاہتا  
 ہوں - سدن میں اس کا جواب تو  
 نہیں مل پائے گا - مالک ادھیکاروں  
 کا میں برا حاسی ہوں - عامہردار  
 ہوں - پریس کو نہ شامل پریس کہا  
 جاتا ہے لیکن میں تو اس کو  
 کہتے ہیں پریس مانگتا ہوں - میں  
 چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ اقلیتوں  
 کی جائدادوں پر جس قدر ظلم ہو  
 رہا ہے اور ان کی اکونومک اور سوشل  
 حالت جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ  
 کے لئے بھی کہا آج تک یہ نام نہادی  
 نہ شامل پریس نے کچھ لکھا ہے -  
 کہا ہم ہندوستان کے شہری نہیں  
 ہیں - چھپ کوئی فساد کا معاملہ

پہنچا ہوتا ہے گزبوی پہنچا ہوتی ہے  
 پریس والوں کو پہنچو ڈالر نظر آتے  
 ہوں۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ  
 بھی بتایا ہے کہ کئی مسلمان اور  
 کئی غور مسلمان ملک کے باہر ہیں  
 اور وہ کئی پھترو ڈالر الگ الگ  
 ہندوستان میں بھرتے ہیں۔ جب  
 پھترو ڈالر کا الزام لگایا جاتا ہے تو  
 یہ بھی بتایا جانا چاہئے کہ کئی  
 مسلمان ہندوستان کے باہر ہیں اور  
 کئی غور مسلمان باہر ہیں اور دونوں  
 الگ الگ کئی پھترو ڈالر ہندوستان  
 میں لاتے ہیں یا بھرتے ہیں۔  
 پریس کی آزادی کا میں بوا حامی  
 ہوں علمبردار ہوں۔ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۷ء  
 تک میں ممبر رہا ہوں۔ پارلیامینٹ  
 کی کابینہ گواہ ہیں کہ میں اسمبلی  
 اور مہتمم نوری پھترو کا ہمیشہ حامی  
 رہا ہوں۔ گورنر صاحب مسٹر تھ  
 دیگر لوگ بھی وہی شکلا ہی بھی  
 تھے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ  
 میں کئی بوا علمبردار اسمبلی  
 مہتمم نوری پھترو کا رہا ہوں اور اس  
 چیز کو پارلیامینٹ کی پروسیجرنگ  
 بھی ثابت کر دیگی لیکن یہ نام نہادی  
 لہشل پریس والوں کو کون سمجھائے۔

درا کلو کھڑی کا معاملہ ملی  
 میں ابھی بھی پمٹنگ ہے۔ دوسرا  
 کوئی ڈرگز کر سکتا ہے لیکن میں  
 نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو ڈرگز  
 کر دیا جائے۔ اہم معاملہ ہے۔ اس

کو میں ڈرگز ہونے بھی نہیں دینگا۔  
 ۲۹ تاریخ کو پچھلے مہینے کی میں  
 خود ویاں گیا تھا۔

میں ڈرگا شریف گیا تھا کلو  
 کھڑی میں ڈرگا کے علاقہ چھوٹے  
 چھوٹے تھستان بھی ہیں۔ تی۔ تی۔  
 اے۔ کے بلڈرز شان سے چل رہے تھے۔  
 جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے چار  
 پانچ دیوارتہ مدت میں ایسے لوگ  
 ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر  
 ہم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن  
 میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں  
 انڈیا کمزور جان نہیں ہوں میں آسانی  
 سے ختم ہونے والا نہیں ہوں ہندوستان  
 سے وہ چاہے وہ کئی کوشش کریں  
 چاہے کئی دنکا فساد کریں۔ ہم جس  
 قوت پر یقین کرتے ہیں اس کا ایمان  
 ہے سوشلزم پر اور سیکولرزم پر۔

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

اگر وہ ایک شہری فورسز میں ڈرانا  
 ممکن چاہتی ہیں تو جمیل الرحمن  
 اور اس کی سات پشتہن کے لوگ  
 قتلے والے نہیں ہیں۔

کلو کھڑی کا مزار ایک متروک  
 مقام ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ۲۹  
 تاریخ کو میں گیا تھا مزار میں  
 جلی تھیں ہیں۔ ابھی سرائے پھر

## [شری جمیل الرحمن]

صاحب کے مزار وہ سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دی گئی ہیں۔ پہلے کے پانی کا جو کوئی تھا اس کو توڑ کر ہراڑ کر دیا گیا ہے۔ انڈیا ہی نہیں وہاں چار پیپل کے درخت ہیں۔ ان کے چاروں طرف چھوٹا بنا دیا گیا ہے اور مزار کو بدل کر دیا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیں۔ کہ یہ کس بات کا سلکھت ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو قہروں کو ختم کیا جا رہا ہے کہیں کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری طرف پیپل کے درختوں کے چاروں طرف چھوٹا بنا کر قہروں بچایا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اس لئے موری گزارش ہے کہ مسٹر صاحب مہربانی فرما کر کمپروہیڈسویل لائٹس۔ شعر کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دم خاک ہو جائیں گے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ سرکار لیمٹیشن پوریت کو بڑھانی جائے اور فی۔ فی۔ اے۔ آرکھولوجیکل ڈیپارٹمنٹ اور ورکس اینڈ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ سب وقف کی خالی زمینوں اور مکاؤں پر قبضہ کرتا جائے اور کوئی جائداد ہی نہ بچے تو مقدمہ کس بات کا یہ بات میں سلکھت کے طور پر کہہ دیا ہوں۔

ابھی آنریبل مسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دلی وقف بورڈ نے دلی ایڈمنسٹریشن کو ایپروچ کیا اور اس لئے ضرورت پڑی کہ وقف ایکٹ میں ایملنڈمنٹ لا کر اس کو لیمٹیشن ۱۹۸۵ ع کے آخر تک بڑھا دیا جائے۔ مسٹر وزیر صاحب کو شکوہ کس سے ہے۔ ہم لوگوں سے یا اس سڈن سے۔ جو آدمی مسٹر کے کف کھڑے میں کھڑا ہے جو اس کام کو کرا رہا ہے لہذا ڈیولپمنٹ ورک وہی ایپروچ کر رہا ہے کہ اس ایکٹ کو بڑھایا جائے۔ اس کی نیت بہت خراب ہے کہ ٹائم کو ایکسٹنڈ کر کے موقع ملے اور ایکوائٹر کر کے مسلمانوں کی ساری جائداد کو نہست و نابود کر دیا جائے نہ رہے گا ہانس نہ بچے گی ہانسری۔

مہرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنا چاہئے ہے ہماری پارٹی کا اصول ہے اور یہی ہماری نیت کا اصول ہے اور ہم اور ہماری پارٹی اس کے بارے میں کسی سے کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ہماری پارٹی اور ہماری نیت اس غلط رویہ کے خلاف ہو وہ قدم اٹھا سکتے ہیں جو جائز اور درست ہیں۔

श्री कमला मिश्र मधुकर (मातीहारी) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। हम और हमारी

पाटीं इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि अल्पमत समुदाय, चाहे वह कोई भी अल्पमत समुदाय हो, के हुकूम की हिफाजत करने के लिए---धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और दूसरे हुकूम---सहयोग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए और उनका द्रढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए ।

जनाब जमीलुर्रहमान साहब ने अपने भाषण में वक्फ की बात तो कही है, जिनकी मैं तार्किक करता हूँ, मगर उसके गलावा अपनी, अपनी पाटीं और अपनी नेता की बात कही है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपकी नेता है, आपकी पाटीं है और आप है, यह कानून चार पांच बार क्यों बदलना पड़ा ? आज तक दिल्ली में सर्वे क्यों नहीं हुआ ? क्यों सरकार थी या नहीं थी ? इन्दिरा गांधी थीं या नहीं थीं ? आप थे या नहीं थे ? यह क्यों बार बार कानून पास करना पड़ रहा है ?

आप ने ही पूछा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या गारंटी है कि 85 के बाद फिर यह कानून बदलना नहीं पड़ेगा ? मेरा पहला प्रश्न है कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो वह इस बात को स्पष्ट करें कि यह सर्वे कब तक समाप्त हो जाएगा और कब तक यह जो प्रापटीं है जो दबायी गई है, जिस का इस्तेमाल मुस्लिम अवाग के विकास के लिए नहीं हो रहा है उस की गारन्टी कब होने जा रही है ? जब तक यह गारन्टी नहीं देंगे पार्लियामेंट आएगी, कानून बनेंगे, बदलेंगे लेकिन जिस सवाल के लिए आप को बैचनी है, वह बैचनी दूर होने वाली नहीं है । इस बात को आप समझ रखिए ।

मौलाना साहब ने सही कहा है कि वक्फ की सम्पत्ति दो किस्म की है । जो सम्पत्ति आप के वारिस को मिलने वाली है उस सम्पत्ति को ले कर आप गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं है । इस लिहाज से हम यह कह रहे हैं, हम जानते हैं, वक्फ की सम्पत्तियों के ऐसे ऐसे तजर्बे मिले हैं कि क्या कहा जाए ? मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह सकता हूँ जो मुस्लिम मजहब के हैं लेकिन हम जानते हैं कि

मन्दिरों और मठों में राम और लक्ष्मण में भगड़ा होता है । लक्ष्मण कहते हैं कि यह हमारी प्रापटीं है और राम कहते हैं कि हमारी प्रापटीं है । और वह भगड़ा कौन तय करता है ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब उस भगड़े को तय करते हैं । कितनी बदतर हालत मठों की हो गई है ?

बिहार में बोध गया में मठ है, उस में हजारों हजार एकड़ जमीन है । मैं जानता हूँ मधुबनी जिले के बोर्डर पर एक मठ है जिस में हजारों हजार एकड़ जमीन है । हद-वन्दी कानून बिहार में लागू करने की बात हो रही है । लेकिन मठों के हाथी के नाम पर, बैल के नाम पर, घोड़े के नाम पर बांट कर सारी जमीन हड़प ली जाती है । उस से उस सम्प्रदाय विशेष के जिस के लिए मठ की कल्पना की गई, मन्दिरों की कल्पना की गई जिस के विकास की और जिस की संस्कृति और सभ्यता के विकास की कल्पना की गई वह पूरी न हो कर ये सारी चीजें आज लूट का साधन बन गई हैं । माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है, उन के यहाँ भी ऐसी बुराई है । मैं जानता हूँ अपने जिले के बारे में, वहाँ एक मदरसा है, उस की कोई कमेट्री थी, उस के सेक्रेटरी ने 25 हजार रुपया हजम कर लिया । उस के बाद तमाम धार्मिक और कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती रहीं, लेकिन आज तक उस ने वह रुपया नहीं दिया । न देने के बाद भी आज वह उस मदरसे को हजम किए हुए है ।

वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उन बातों में भी सुधार लाने के लिए विधेयक लाना चाहिए । इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने मांग की है कि एक कामग्रीहसिज बिल लाना चाहिए, वह सही है । यह पंचन्द लगाने से काम नहीं चलेंगा । भोजपुरी में एक कहावत है थक चाटने से प्यारा नहीं जाती है । ऐसे ही यह थारा ऐसे नहीं बुझने वाली है । आप वाज्जान्त बिल लाइए । सारे देश के वक्फ में चलने वाली गड़बड़ियों को दूर कीजिए । पुराने जमाने में खलीफों के वक्त में यह वक्फ बना जहाँ तक मैं जानता हूँ लेकिन जिस

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

मकसद के लिए बना वह मकसद पूरा होना चाहिए, हिन्दुस्तान में भी पूरा होना चाहिए। अगर आप सचमुच चाहते हैं डेमोक्रेसी को चलाना तो डेमोक्रेसी का जकाज है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ जैसे जमीनुर्रहमान साहब भाषण दे कर चले गए। हम इस को सूझ बुझ की बात मानते हैं। हमारी पार्टी इस को सिद्धान्त की बात मानती है और सिद्धान्त के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ऐसी बात होनी चाहिए।

इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि वक्फ बोर्ड को कोई लीगल पोजीशन आज नहीं है, वह कह दे तो वह कमिश्नर के यहां जाए, कलेक्टर के यहां जाए, उसका नतीजा हो रहा है कि जो सम्पत्ति ली गई है वक्फ की, जिसका दुरुपयोग हो रहा है उस को वह लोग एविकट नहीं कर सकते हैं। उन को पावर नहीं है। इस बात पर सोचना चाहिए सरकार को कि उन को कोई कनूनी अधिकार मिलना जारी है या नहीं मिलना जरूरी है ?

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड को डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। राज्य सभा में भी इस संबंध में मांग उठाई गई थी। दिल्ली में ही जो वहां की मस्जिदें हैं, वहां के स्थानीय मुसलमानों को लेकर और वहां के वक्फ बोर्ड का चुनाव होना चाहिए। उसका जनतन्त्रीकरण होना चाहिए। ताकि वहां के लोगों को उस सम्पत्ति को लूटने का मौका ही न मिल पाए। दाहन और लूटन---हिन्दू हो या मुसलमान---चलता है धन के नाम पर। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ, वक्फ सम्पत्ति का सर्वे कब तक पूरा होगा ? उसके लिए आप सदन में आश्वासन दीजिए। इस सम्बंध में आप कौसी मशीनरी डवलप करने जा रहे हैं। इतने दिनों तक सर्वे नहीं हुआ है और चार बार आप संशोधन कर चुके हैं। अब संशोधन करने के बाद कौन सी आप नई मशीनरी डवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि 1985 तक सर्वे का काम तेजी के साथ पूरा हो जाए।

इन चीजों को दुरुस्त न कीजिएगा, तब तक मुसलमानों के दिल में जो आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं बनी रहेंगी। उन आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आप की है, इस संबंध में आपको कदम उठाने चाहिए। आपकी पार्टी का नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, उसमें मेल होने के लिए यह जरूरी है कि आप हाउस में आवाज की आवाज को लेकर आए हैं; उस आवाज की गम्भीरता को समझिए। इसको हल्के-फुल्के ढंग से मत लीजिए। यहां लोग आवाज की आवाज को बोल रहे हैं, काम की बात को आपके सामने रख रहे हैं। उन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप यह बिल सदन में लाए हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं भी इसके हक में हूँ और जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनके बारे में आपको सफाई करनी चाहिए। जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का समाधान आपके जवाब में होना चाहिए, ताकि आइंदा बिल का एक्सटेंड करने की जरूरत ही न पड़े। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री मुजुफ्फर हुसैन (बहराइच) :  
जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत अपनी हुकूमत की जवज्जह न सिर्फ दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूँ, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के वक्फ की ओर भी दिलाना चाहता हूँ।

जहां तक दिल्ली के वक्फ का सवाल है, तो किसी शायर ने इसी से मतअशिर होकर कहा है---चेहरें पर सारे शहर के गदें मलाल हैं, जो दिल का हाल है, वहीं दिल्ली का हाल है। उलझन, घुटन, हिरास, तपिश कर्ब इनतेशार, वह भीड है कि सांस भी लेना मुहाल है।

वक्फ के सेलसिले में हमारे सदन के मंम्बरान ने आपके सामने बहुत सी तजवीजें रखी हैं।

श्री जैनुल बशर : सारे इंसान नहीं हैं, कुछ इंसानदार भी हैं।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मुझे बड़े अफ-सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 35 साल गुजर चुके हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर फसादात हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसका न मुझे तजक़िरा करना है और न इतना वक्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग भी हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों का तजक़िरा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप सदन में इसका तजक़िरा करना छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि हमारी आजादी को 35 साल बीत चुके हैं, हमारे जिन्दों का भारतीयकरण करने का बहुत से लोगों ने मनसूबा बनाया था, लेकिन जिसको खुदा रक्खे, उसको कौन चखे। 35 साल आजादी के गुजर जाने के बाद हमारी आबादी चार करोड़ से 15 करोड़ हो गई है और ऐसे लोग जो हुकूमतों की मशीनों में दाखिल हैं, वे हमारे जिन्दों और मुर्दों को भी अपनी कढ़ी में देखना पसन्द नहीं कर रहे हैं। और वे चाहते यह है कि किसी सूरत में इस हुकूमत की पेशानी पर कलंक का टीका लगे। आज मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि डी. डी. ए. और दीगर एजेंसियाँ जो हैं, उन में अगर हिम्मत या ज़रूरत हो, तो ज़रा वे साऊथ ब्लॉक में, साऊथ एवेन्यू में चल कर या नार्थ एवेन्यू में चल कर किसी गुरुद्वारे की दीवार को हाथ तो लगा दें, किसी मन्दिर को तोड़ दें, किसी मन्दिर पर बलडोज़र चला दें, किसी को गिरा दें? किसी में हिम्मत है कि वह इस को कर सके। फिर क्या वजह है कि हुकूमत के साथे मैं, हुकूमत की निगरानी में, हुकूमत को देखते हुए, जहाँ मिनिस्टर मौजूद हैं, जब वहाँ कोई मन्दिरों को हाथ नहीं लगा सकता, गुरुद्वारों को काँडे छू नहीं सकता, हमारी मस्जिदों पर आप की मशीनें चल रही हैं और हमारे बाप-दादाओं की हीड्डियों पर आप को मोटर चल रही है, जिन पर आप ने हजारों पूल बनवा दिये और हजारों सड़कें बनवा दी। तो मैं समझूँगा कि इस हुकूमत के, जिम्मेदार लोगों के मन में मुसलिम कौम से कोई हमदर्दी है या नहीं? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारा घर है और निगरानी आप की है मैं कल देख कर

आया हूँ। मस्जिदों में होटल बने हुए हैं। मैं कल देख कर आया हूँ कि नई दिल्ली स्टेशन से जाते हुए रास्ते में मस्जिदों में कारखाने बने हुए हैं। न जाने हजार बार यहाँ के मुसलमानों ने इस तरफ तबज्जह दिलाई लेकिन सिवाय डी. डी. ए. के कब्जे के और कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं डी. डी. ए. को ही कसूरवार नहीं ठहराऊँगा बल्कि जो सुन्नी मजलिसों का काफ़ के जो जिम्मेदार है, वह भी कसूरवार है इस चीज के लिए। पहले तो डी. डी. ए. को कब्जा करते वक्त, वे मुकदमा दायर करते हैं, मदाखलत करते हैं लेकिन बाद में समझौता कर के उन से रुपया ले कर मस्जिद और कब्रिस्ताभ बेच डालते हैं। इसलिए जहाँ डी. डी. ए. मूजरिम है, वहाँ साथ ही साथ सुन्नी मजलिसों का काफ़ भी मूजरिम है। यह बात नहीं है कि उन को अपना समझ कर मैं माफ करूँगा। वे इन्हें सब से बड़े कसूरवार हैं क्योंकि वे हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को डी. डी. ए. से पैसा ले कर बेच रहे हैं। ऐसे वक्त बोर्ड को तो देना चाहिए। उन को हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को जाय-दाद पर डी. डी. ए. का कब्जा कराए और हुकूमत को बदनाम करें।

दूसरी गुज़ारिश इस सिलसिले में मैं यह करूँगा कि जहाँ तक सुन्नी मजलिसों का काफ़ का तालुक है, 1961 के अन्दर इसी लाल किले के मैदान में मैं ने एल आल इन्डिया सुन्नी आँकाफ कान्फ़ेन्स का थी, जिस जमाने में पं. जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और हाऊसिंग मिनिस्टर माननीय श्री मेहर चन्द खन्ना थे। हम तीन दिन की कान्फ़ेन्स के बाद सारे मेमों रेण्डम ले कर पंडित जी की खिदमत में हाजिर हुए। पंडित जी ने हमारे मेमों रेण्डम को बहुत गौर से पढ़ा हम ने सन् 1947 से पहले दिल्ली की सर-जमीन पर जितनी मस्जिदें मौजूद थी, जितने कब्रिस्तान मौजूद थे, उन के फोटो लिए और सन् 1947 के बाद जो मस्जिदें और कब्रिस्तान मुस्लिम शकलों में तब्दील किये गये थे, जिसका कितावचा बाजावता फोटो के साथ मेरे पास अब भी मौजूद है, उन के

[श्री मुज्फर हुसैन]

दिखाया। पंडित जी ने और मेहर चन्द खन्ना साहब ने, हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को उन रिफ्यूजीज से, जो मस्जिदों में आबाद हो गये थे और कब्रिस्तानों में जिन्होंने दुकानें बना ली थी, खाली करा कर मजलिसे आकाफ को दे दिया। दो साल तक पंडित जी जिन्दा रहे और सन् 1964 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता खामाशी के साथ उन पर गवर्नमेंट की एजेन्सियां काबिज होती गईं और जबर्दस्ती पुलिस के जरिये कब्जा करती गईं। मुसलमान निहत्थे, परेशान-हाल उन का मुकाबला न कर सके और इस तरीके से आज भी वे काबिज हैं। मेरे पास दिल्ली की 700 मस्जिदों की लिस्ट मौजूद है, जिन पर आज भी गैरों का कब्जा है। इस अन्दाज में कि उन मस्जिदों में कहीं पर होटल है, कहीं मोटर के कारखाने हैं या टी-स्टाल हैं और जो बड़ी मस्जिदें हैं, तो उनमें लोगों ने अपने रिहायशी मकान बना लिए हैं और कुछ मस्जिदों में लोग पाखाना फिर रहे हैं। तो इस की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। अगर इस के जेरे-साये 15 करोड़ मुसलमानों की जिन्दगी, महफूज न हो और अगर हमारी मस्जिद, हमारे मक़ातिब, हमारे कब्रिस्तान, हमारी इबादतगाहें और हमारे आषा-औ-अजदाद के आस्ताने आप की हुकूमत में महफूज न रहें, तो आप हम से क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आप का साथ देंगे। क्या मुसलमान इसलिए पैदा किया गया है हिन्दुस्तान की सर-जमीन पर कि जब इलेक्शन आ जाए, तो उन के वोट ले कर आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाएं और जब इलेक्शन खत्म हो जाए, तो उस को जिन्दों व मर्दों को भी इस सर-जमीन पर भी न रहने दिया जाए। . . . (व्यवधान) . . . हमारी सरकार हो या कोई सरकार हो, अगर हमारी सरकार की खामी है, उस में कोई कमी है, तो मुझे वह कहने में उज्र नहीं। इसलिए कि मैं हिन्दुस्तान का वासी हूँ न कि पाकिस्तान का और न बंगलादेश का। इस मुल्क में अगर दूसरी कोमों के कर्बानियां दी हैं तो मुसलमान काम की कर्बानियां भी किसी से कम नहीं हैं। हमारा हक है कि हम अपने हक को हासिल करें हम इस मुल्क के हकदार हैं। आपका यह फर्ज है कि आप हमारी हिफाजत करें।

मैं आप से अर्ज करता हूँ कि आप वक्फ को तोड़ दें और सब में और हर कमिश्नरी में वक्फ कमिश्नर म्करर कर और कमिश्नर गैर-मुसलिम हों। एक गैर-मुसलिम के दिल में दर्द होगा। लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद को खूद बेच देता है। अगर हिन्दू कमिश्नर होगा तो उसके दिल में दर्द होगा कि मुसलमान हमारे देश से न जान पायें, मुसलमानों की जायदाद तल्फ न होने पाये। लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद खूद बेच देता है। उसके दिल में दर्द नहीं होता। औरों के दिल में खूदा का ख़ाफ होगा, मुसलमानों की मस्जिदों की, जायदादों की हिफाजत करेगा। आप इन वक्फ बोर्ड को तोड़ दीजिए और किसी भी मुसलमान को वक्फ कमिश्नर मत बनाइये। हिन्दू, सिख, ईसाई किसी भी काम के आदमी को वक्फ कमिश्नर म्करर कीजिए ताकि वे हमारे मजहब, हमारे जजबात का लिहाज करें, हिफाजत करें। वे हमारी जायदादों की हिफाजत करेंगे, उनमें डर होगा कि अगर हमने इन्हें तोड़ डाला या बेच डाला तो वगावत फैल जाएगी। उस से हमारी जायदादें महफूज रहेंगी। अगर किसी मुसलमान को आप बना देंगे तो मुसलमानों को न खूदा का ख़ाफ है, न रसूल ख़ाफ है, न मजहब का ख़ाफ है। वे अपने बाप-दादाओं की जायदादों को भी बेच डालेंगे और उनका दिल में दर्द भी नहीं होगा।

**श्री अनुराध बशर:** आप सब मुसलमानों को बेईमान क्यों कहते हैं? कुछ मुसलमान बेईमान हो सकते हैं।

**श्री संयव मुज्फर हुसैन :** मैं सब जगह की बातें जानता हूँ। उत्तरप्रदेश का इरा से भी बुरा हाल है। दिल्ली में तो जायदादें और मस्जिदें बेच ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप से कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड को तोड़िये और वक्फ कमिश्नर म्करर कीजिए जिससे कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जायदाद की हिफाजत हो सके और मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबीयत हो सके। इस से सही मायनों में मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत हो सकेगी और उनसे होने वाली आम्दानी भी सफ हो सकेगी। इसका इस्तेमाल भी

वाकिफ की मन्शा के मुताबिक हो सकेगा । इस तरह से हमारी जायदाद महफूज हो जाएगी । दरना चाहे आप डी. डी. ए. के हाथ में डालें और किसी और एजेंसी के हाथ में डालें, हम आप से शिकवा करेंगे और आप उनसे कुछ कह न सकेंगे ।

मैं आप से गुजारिश करूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश में हों, चाहे बिहार और गुजरात में हों, चाहे दिल्ली में हों, आपने वक्फ बोर्ड में सब उन्हीं लोगों को रखा है जिनको कि आप समझते हैं कि आजादी के पहले इन्होंने हमारा साथ दिया था । मैं आप से कहता हूँ कि अगर आपको उनकी परवरिश करनी है तो कीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है । नेपाल के बार्डर पर बहुत मैदान पड़े हैं, वहां उन्हें जगह दीजिए । वहां वे खेत बाँए, जोतें और अपना गुजर करें । लेकिन आजादी के लिए दी गई कुर्बानी के लिए हमारे बाप-दादाओं की जायदाद बेचने का उनको हक हासिल नहीं है ।

मैं आप से फिर गुजारिश करता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड तौड़िए और वक्फ कमिशनर मुकर्रर कीजिए । दिल्ली की सारी मस्जिदों और जायदादों के लिए आप पार्लियामेंट के 11 मंम्बरान की एक निगरान कमिटी बना दीजिए जो अपनी निगरानी में, बजरिए पुलिस कमिश्नर उनको खाली करा सके । इस से आपकी जम्हूरियत की लाज बचेगी और मुसलमानों की जायदादों की भी हिफाजत होगी ।

बस मुझे यही अर्ज करना है ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोत-रम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर जिस तरह से बहस हो रही है, उसके मूआफिकतमें खड़ा हुआ हूँ । मूआफिकतन करने का मतलब यह है कि जायदादों का भाँका दे दिया जाए कि उनके लिमिटेशन खत्म हो कर के वे दूसरों के हवाले हो जाएं । इसलिए मैं इसकी मूआफिकतमें खड़ा हुआ हूँ ।

जहाँ तक वक्फ की जायदाद का सवाल है और उस पर गार्सिबाना कब्जे का सवाल है,

हमारे और साथियों ने, मौलाना साहब ने, जमीलुर्रहमान साहब ने, जैनल बशर साहब ने उसका जिक्र किया है । इधर के साथियों ने भी जिक्र किया है । इस सब पर बहस हुई है । मैं इस पर बोलते हुए एक बहुत भारी शस्सियत का एक खत पढ़ कर सुनाना चाहूँगा कि किस तरह से वक्फ की जायदाद पर सरकार के अहलकार सरकार के महकमे कब्जा किये हुये हैं । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शस्सियत, हुकूमत की वजीरेआजम के कहने, खत लिखने के बाद भी उनके कान पर जूँ तक नहीं रंगी । मैं उन खत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1974 में सबों के, रियासतों के वजीरे-आला और मर्कजी टैरिटरीज का लिखा था । श्रीमती गांधी ने लिखा -

"I am deeply concerned over the fact that Wakf properties are under undue occupation of illegal occupants."

यहीं तक बात नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिखा है -

"The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and local bodies."

बाद में फिर उन्होंने उसी खत में कहा -

"I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

यह 1974 की बात है और 1974 से अब तक 8 साल का समय गुजर चुका है । ऐसा लगता है जैसे कि कल इस सदन में कौपिटेशन फीस के बारे में बहस हो रही थी । कौपिटेशन फीस के मामले में प्रधान-मंत्री की मर्जी है, केन्द्रीय सरकार की मर्जी है, और यहाँ तक कि बिहार सरकार की भी मर्जी है, कि कौपिटेशन फीस न ली जाये, लेकिन कौपिटेशन फीस ली जा रही है । बिहार, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश जहाँ फीस

[श्री अशाफाक हुसैन]

ली जा रही है वहां तो मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही, लेकिन इस मामले में तो दिल्ली में जहां सीधी हुकूमत केन्द्रीय सरकार की है, अफसोस की बात है कि वहां भी प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही है।

तो मामला इतना अहम है कि उसके लिए जरूरी है कि कारगर कदम, फॉरी कदम उठाए जाएं। जो सर्वे इन वक्त हो रहा है और जो एक्सटेंशन की बात कही गई है, इस विल के जरिये, मेरी जानकारी में 31 दिसम्बर 1981 तक 2447 वक्फ की जायदाद दिल्ली के अंदर सर्वे हुई और उनमें से 1811 का गजट भी हो गया, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि गजट होने के बाद कब्जा कितनी जायदादों पर वक्फ बोर्ड को दिया गया? और अगर नहीं दिया गया तो पोजीशन क्या है और क्या इसमें ज्यादातर डी. डी. ए. और सरकारी महकमे शामिल नहीं है?

दूसरा सवाल लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में है हमारे साथी श्री जैनल बशर जी ने इसका हवाला दिया और एक खतरनाक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद को भी एक्वायर कर लिया गया। तो अगर सरकार की वाक्यी नीयत है कि मुस्लिमों के पर्सनल ला में कोई दखलअंदाजी न की जाए तो लैण्ड एक्वीजिशन के जरिए मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और इबादतगहों या इरा तरह की और जगहों का लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट से मुस्तसना क्यों नहीं किया जाता। मैं मांग करूंगा कि इनको लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट से मुस्तसना किया जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वजीरे आजम इस के बारे में खत लिखती है लेकिन दूसरी तरफ अभी पिछले महीने राज्य सभा में एक सवाल पेश हुआ था जिस में पूछा गया था कि बनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है जिस के जवाब में यह बताया गया था :

“The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee

Report with respect to the properties claimed by Delhi Waqf Board in phases.”

आप फौजज में करेंगे या एक साथ करेंगे, इस पर बुनियादी एतराज की कोई गूँज इश नहीं है। लेकिन सब से ज्यादा खतरनाक पहलू जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह खतरनाक बात यह है कि आपकी जुबान से निकल गया जानबूझ कर या बिना जान बूझे इसका मत-  
“But which are not required for the planned development of Delhi.”

लब यह है कि वही जायदाद हवाले की जाएंगी बनी रिपोर्ट के मुताबिक जिन की दिल्ली के प्लान्ड डिवेलेपमेंट के लिए जरूरत नहीं होगी। आप समझ लें कि दिल्ली का प्लान्ड डिवेलेपमेंट ऐसा हाथी है, ऐसा परदा है जिस के पीछे सारी वक्फ की जायदाद हड़प की जा सकती है और उनको हड़प करने की साजिशें भी की जा रही हैं। इससे आप हॉशियार रहें।

गवर्नमेंट का एक कानून है :

Public Premises Eviction of Illegal Occupation Act.

वक्फ किसी एक आदमी की जायदाद नहीं होती है। अगर वाकई मैं आप वक्फ की जायदादों का कुछ तस्फिया चाहते हैं तो वक्फ की जायदादों का तस्फिया ला कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में नहीं हो पाएगा। आज तक का तजुर्बा यह है कि बीस-बीस साल तक पच्चीस-पच्चीस साल तक मुकदमे चलते रहे हैं और चलने के बाद भी वक्फ बोर्ड या दूसरे इदारें उनका तस्फिया नहीं करा सकते हैं। मेरी मांग है कि वक्फ की जायदादों को यह जो एक्ट है इसके तहत लाया जाए और खाली कराया जाए क्योंकि ये भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं।

कुछ लोगों में खुशफहमी है और वे समझते हैं कि वक्फ की जायदाद इतनी है कि इन से मुस्लिम कॉम की तालीम का, समाजी बहबूदी का सारा इंतजाम हो सकता है और उस में शायद मदद की जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन

پہلے بنگلہ دیش میں آیا تھا کہ 75 لاکھ  
کی وکف کی آمدنی میں سے دہلی میں  
ایک نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولا  
جائے گا۔ سچائی یہ تھی اسکا کیا ہوا؟

Rs 75 lakh Waqf Vocational Training  
Institute will be set up in Delhi soon.

کیوں یہ اسکیم عمل میں نہیں آئی۔  
دہلی وکف بورڈ کی طرف سے شاید یہ  
شایا ہوا تھا یا دہلی وکف بورڈ کی  
طرف سے اس کو کسی نے شایا کرایا تھا۔  
تو کیا رپیا نہیں تھا؟ اگر رپیا نہیں  
تھا تو اس طرح کی خبر اقامت میں غلط  
فہمی پیدا کرنے کے لیے نہیں دینی چاہیے۔

میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا اور  
مন্ত্রী جی سے چاہوں گا کہ اس پر غور کرے  
کہ وکف کا ایک کامپریہنسو کانون وہ  
لائے، اور میں جو ممبروں نے ان کو  
سلاہ دی ہے اور سदन کے لوگوں نے جو اپنی  
بات کہی ہے، اس پر وہ دھیان رکھیں گے لے-  
کین ایک بات اور وہ دھیان میں رکھے، اس  
پر غور کرے کہ کیا وکف کے کانون کو  
ساری پابندیوں سے بچانے کے لیے کانسٹیچوشن  
کے ناڈنٹھ شڈیول کے اندر لایا جا سکتا  
ہے؟ اس پاسیبلٹی پر بھی وہ غور  
کرے۔ جب کہ لڈ سلیٹنگ ایکٹ اور  
تمام طرح کے کانونوں کو تھفوج دینے کے  
لیے کانسٹیچوشن کے ناڈنٹھ شڈیول کا  
استعمال کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے  
اس وکف کے کانون کو بھی وہ ناڈنٹھ شڈی-  
ول کے تحت لائے۔

ان شब्दوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم  
کرتا ہوں۔

شری اشفاق حسین (مہاراج کلج):

محترم قومی اسپیکر صاحب - اس  
بل پر جس طرح سے بحث ہو رہی  
ہے میں اس کی موافقت میں کھڑا  
ہوا ہوں۔ موافقت نہ کرنے کا مطالبہ  
یہ ہے کہ جائدادوں کو موقع دے دیا  
جائے کہ ان کے لئے مشن ختم ہو کرے

دوسروں کے حوالے ہو جائیں۔ اس  
لئے میں اس کی موافقت میں کھڑا  
ہوا ہوں۔

جہاں تک وقف کی جائداد کا  
سوال ہے اور اس پر فاضلانہ قبضے کا  
سوال ہے ہمارے اور ساتھ میں نے مولانا  
صاحب نے جمیل الرحمن صاحب  
نے زمین الیہر صاحب نے اس کا ذکر  
کیا ہے ادھر کے ساتھ میں نے وہی ذکر  
کیا ہے۔ اس سب پر بحث ہوئی  
ہے۔ میں اس پر بولتے ہوئے ایک  
بہت بھاری شخصیت کا ایک خط  
پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ کس طرح  
سے وقف کی جائدادوں پر سرکار کے  
اہل کار سرکار کا محکمہ قبضہ کرتے ہوئے  
ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی  
شخصیت حکومت کی وزیر اعظم کے  
کہنے کے خط لکھنے کے بعد وہی ان کے  
کان پر جوں تک نہیں دینگے۔ میں  
اس خط کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر  
سنانا چاہتا ہوں جو پردھان منتری  
شریمتی اندرا گاندھی جی نے ۱۹۷۴ء  
میں صوبوں کے - ریاستوں کے وزیر  
اہلی اور مرکزی ٹیریٹریز کو رکھا تھا۔  
شریمتی گاندھی نے لکھا۔

"I am deeply concerned over the  
fact that Wakf properties are under  
undue occupation of illegal occupants."

میں تک بات نہیں ہے انہوں نے  
صاف صاف لکھا ہے۔

"The most distressing fact is that  
some of the properties are under the  
occupation of Government and local  
bodies."

## [شری اشفاق حسین]

بعد میں یہ انہوں نے اسی خط میں کہا -

"I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

۱۹۷۳ء کی بات ہے اور ۱۹۷۴ء سے اب تو آٹھ سال کا سہ ہوا چکا ہے - ایسا لگتا ہے جیسے کہ کل اس سدن میں کمیٹیٹیشن فیس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی - کمیٹیٹیشن فیس کے معاملے میں پردھان منتری کی مرضی ہے کہلدریہ سرکار کی مرضی ہے اور یہاں تک کہ بہار سرکار کی بھی مرضی ہے - نہ کمیٹیٹیشن فیس نہ لی جائے لیکن کمیٹیٹیشن فیس لی جتا رہی ہے - وہاں تو مان لیا جائے کہ پردھان منتری کی رت نہیں چل رہی لیکن اس معاملے میں تو دلی میں جہاں سڈھی حکومت کہلدریہ سرکار کی ہے افسوس کی بات کہ وہاں بھی پردھان منتری کی رت نہیں چل رہی ہے -

تو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ کارگر قدم فوری قدم اٹھائے جائوں - جو سروے اس وقت ہو رہا ہے اور جو ایکٹیشن کی بات کہیں کہی گئی ہے اس بل کے ذریعہ مہری جانکاری میں ۳۱ دسمبر ۱۹۸۱ء تک ۲۳۲۷ وقف کی جائدادیں دلی کے اندر سروے ہوئیں اور ان میں سے ۱۸۱۱ کا کٹ بھی ہو گیا لیکن میں

یہ جاننا چاہوں گا کہ کٹ ہونے کے بعد قبضہ کئی جائدادوں پر وقف بورڈ کو دیا گیا - اور اگر نہیں دیا گیا ہے تو پوزیشن کیا ہے اور کیا اس میں زیادہ تر قی - قی - اے - اور سرکاری محکمے شامل نہیں ہیں -

دوسرا سوال لہڈ ایگزیوشن کے بارے میں ہے - ہمارے ساتھی شری زمین الہدر جی نے اس کا حوالہ دیا اور ایک خطرناک پہلو کی طرف دھیان دلایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے مسجد کو بھی ایکوائٹر کر لیا گیا - تو اگر سرکار کی واقعی نیت ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے تو لہڈ ایگزیوشن کے ذریعہ مسجد قبرستان عید گاہ اور عبادت گاہوں یا اس طرح کی اور جگہوں کو لہڈ ایگزیوشن ایکٹ سے مستثنیٰ نہیں کیا جاتا - میں مانگ کروں گا کہ ان کو لہڈ ایگزیوشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیا جائے لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کے بارے میں خط لکھتی ہیں لیکن دوسری طرف ابھی ابھی پہلے پہلے راجیہ سبھا میں ایک سوال پٹھی ہوا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ برنی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر سرکار کیا کرے جا رہی ہے جس کے جواب میں یہ بتایا گیا تھا -

"The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee Report with respect to the properties claimed by Delhi Wakf Board in phases."

آپ ڈھنڈے میں کریں گے یا ایک ساتھ کریں گے اس پر باہمی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک پہلو جو ہے اس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ وہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکل گیا جان بوجھ کر یا بدلا جانے بوجھ۔

"But which are not required for the planned development of Delhi."

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جائدادیں حوالے کی جائیں گی ہرنی رپورٹ کے مطابق جن کی دلی کے پلاننگ ڈیولپمنٹ کے لئے ضرورت نہیں ہو گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دلی کا پلاننگ ڈیولپمنٹ ایسا ہائی ہے ایسا پودا ہے جس کے پھچھ ساری وقف کی جائدادیں ہرپ کی جا سکتی ہیں اور ان کو ہرپ کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ گورنمنٹ کا ایک قانون ہے :

Public premises Eviction of Illegal Occupation Act.

وقف کسی ایک آدمی کی جائداد نہیں ہوتی ہے۔ اگر واقعی میں آپ وقف کی جائدادوں کا کچھہہ تصفیہ چاہتے ہیں تو وقف کی جائدادوں کا تصفیہ لا کورٹ میں سور کورٹس میں نہیں ہو سکتا گا۔ آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ ہمس بھس سال تک

پچیس پچیس سال تک مقدمے چلتے رہے ہوں اور چلنے کے بعد بھی وقف ہورتے یا دوسرے ادارے ان کا تصفیہ نہیں کرا سکے ہوں۔ مہری مانگ ہے کہ وقف کی جائدادوں کو یہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت لیا جائے اور خالی کرایا جائے کہو، یہ ہی ہلک پریمیزز ہوتے ہوں۔

کچھہہ لوگوں میں خوش فہمی ہے اور وہ سمجھتے ہوں کہ وقف کی جائدادیں اتنی ہیں کہ ان سے مسلم قوم کی تعلیم کا سماجی بہبود کا سارا انتظام ہو سکتا ہے اور ان میں شاید مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھہہ دن پہلے اخباروں میں آیا تھا کہ ۷۵ لاکھ کی وقف کی آمدنی میں سے دلی میں ایک وکھشل ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ کھولا جائے گا۔ سوخی یہ تھی۔

Rs. 75 lakh Wakf Covational Training Institute will be set up in Delhi soon.

اس کا کہا ہوا۔ کہوں یہ اسکیم عمل میں نہیں آئی۔ دلی وقف ہورتے کی طرف سے شاید یہ شائع ہوا تھا۔ یا دلی وقف ہورن کی طرف سے اس کو کسی نے شائع کرایا تھا۔ تو کھا روپیہ نہیں تھا۔ اگر روپیہ نہیں تھا تو اس طرح کی خیر عوام میں قلم فہمی پودا کرنے کے لئے نہیں دلی چاہئے۔

[شہری اشفاق حسین]

میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا اور ملتزمی جی سے چاہوں گا کہ اس پر فور کریں کہ وقف کا ایک کمپورہیلسو قانون وہ لائیں گے اس میں جو ممبروں نے ان کو صلاح دی ہے اور سدن کے لوگوں نے جو ایسی بات کہی ہے اس پر وہ دھمان دکھیں گے لیکن ایک بات اور وہ دھمان میں دکھیں اس پر فور کریں کہ کیا اس وقف کے قانون کو ساری پبلندیوں سے ہچالے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نانڈتھہ شہدروں کے اندر لایا جا سکتا ہے - اس پانچولہٹی پر بھی وہ فور کریں - جب کہ لہذا سہلنگ ایکٹ اور تمام طرح کے قانونوں کو تحفظ دینے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نانڈتھہ شہدروں کا استعمال کیا جانا ہے تو مسلمانوں کے اس وقف کے قانون کو بھی وہ نانڈتھہ شہدروں کے تحت لائیں -

ان شہدروں کے ساتھ میں ایسی بات ختم کرنا ہوں -

SHRI A. A. RAHIM: Sir, The hon. Members who spoke, had the full realization of the importance of the Bill, and have given me full support in respect of this Bill. I take this opportunity to thank the Members at the outset.

Many of the learned Members expressed their feelings about the present state of affairs; and they have got an opportunity to ventilate the position regarding Wakf properties and certain Wakf Boards. They spoke at length about alienation, encroach-

ment and mismanagement of properties. There was a long discussion about Wakf Board properties as such; but those discussions are not really directly related to this Bill. The Government will take due note of the suggestions, and will definitely try to improve the administration.

The amendment of the Wakf Act is already on the anvil, and will be presented to Parliament this year itself. At that time, these points can be discussed in detail. By amending the Act, the present state of affairs can be improved.

There was criticism about the neglect by the authorities, in restoring Wakf properties. I am not having the details of other States; but I am having certain statistics regarding the Delhi Wakf Board's working in this regard. The Delhi Wakf Board filed 577 cases during the five years from January 1976 to December 1980, with the following break-up:

1976	16
1977	3
1978	40
1979	34
1980	484

Altogether 577. Out of the above cases, 157 cases have been decided, of which 108 have been decreed in favour of the Delhi Wakf Board; and 49 cases have been dismissed. The Delhi Wakf Board has gone in appeal in 49 cases which have been dismissed. And when the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1982 is passed, the Delhi Wakf Board proposes to file about 300 more cases for recovery of the possession. As the survey of the Wakf properties is continuing, the number of such cases may again increase.

I take this opportunity to assure the Members that the survey will be expedited, and will be completed soon.

Regarding Burney Committee Report, the Committee submitted its Report in 1976 and in all considered 209 properties. The Government is considering the implementation of the Report in phases. You

will appreciate that there are legal complexities involved. These have to be resolved in the first instance. I can say that something tangible, something positive will be done in this regard. I am expecting cooperation from the members. This Bill is only a step to restore the properties and to protect them and to restore them to the rightful owners.

With these words, I move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI A. A. RAHIM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 A.M. on Monday, the 9th August, 1982.

19.57 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 9, 1982/ Sravana 18, 1904 (Saka).*